मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली राजस्व और उपनिवेशन विभाग की बैठक

बजट घोषणाओं के कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व और उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन, डीपीआर और टैंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर विकास कार्यों का लाभ आमजन तक समय पर पहुंचाया जाए।

■ **प्रदेश में 18 सितम्बर से शुरू होगा ''गांव चलो'' अभियान**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व और उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुड गवर्नेंस के मानकों पर खरा उतरते हुए जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग तकनीक और नवाचार के माध्यम से काश्तकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटा है। किसानों को स्वयं फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एग्रीस्टेक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक किसानों को इस एप से जोड़ा जाए और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 18 सितम्बर से प्रदेशभर में सप्ताह में तीन दिन ''गांव चलो'' अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सीमाज्ञान, सहमति विभाजन, नामांतरण सहित लंबित राजस्व प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस अभियान के लाभ से वंचित न रहे।

बैठक में भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों के बजट में घोषित भवनों का निर्माण कार्य प्राथमिकता से पूरा किया जाए। उन्होंने पुराने भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए ताकि सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। जैसलमेर जिले में सामान्य आवंटन से जुड़े लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए 15 दिन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियमों के सरलीकरण की बात भी कही गई।

अधिकारियों ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री योजना के तहत अब तक 87 प्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी जनरेट की जा चुकी है। किसानों के आधार नंबर को राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ने का कार्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ कर दिया गया है। भू-नक्शा पोर्टल पर अब तक राज्य के 48,463 गांवों की जिओ रेफरेंस शीट फाइल अपलोड कर 4.49 करोड़ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किए जा चुके हैं।

बैठक में रेवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम, राजस्व इकाइयों का पुनर्गठन, सरकारी अधिवक्ताओं को रिटेनर शुल्क, उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन दर में संशोधन, ग्राम दान और भूदान अधिनियम सहित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। बैठक में राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

माँ के अपमान पर जयपुर भाजपा ने हुंकार भरी

छोटी चौपड़ पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला जलाया

भाजपा जयपुर शहर की ओर से मंगलवार को छोटी चौपड़ पर धरना देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी व तेजस्वी यादव पुतला दहन किया गया।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। भाजपा जयपुर शहर की ओर से मंगलवार को छोटी चौपड़ पर विशाल धरना तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी व तेजस्वी यादव पुतला दहन किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पूज्य माता के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों के खिलाफ 3 घंटे चले इस धरने में भाजपा के सभी कार्यकर्ता विधायक व अन्य नेताओं ने अपने भाषण में राहुल गांधी व तेजस्वी यादव की तीखी आलोचना की। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने भारत मां के जयकारे लगाए और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की।

जयपुर जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा कहे गए अपशब्द केवल एक माता का नहीं, बल्कि समस्त मातृ शक्ति एवं भारतीय संस्कारों और संस्कृति का अपमान है। उन्होंने कहा कि माँ का अपमान कॉँग्रेस की पहचान है।

मां के अपमान पर जयपुर की नारी चुप नहीं रहेगी। मां सीता का अपमान होने पर सोने की लंका जला दी गई थी। मां को भरी सभा में घसीटा गया, तो महाभारत हुई। एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री की मां का अपमान हुआ है और यह प्रधानमंत्री की मां का नहीं, बल्कि हर भारतवासी की मां का अपमान है। सनातन को मानने वाला चुप नहीं रहेगा। पुतला दहन के माध्यम से हम सभी को अपने अंदर की बुराई को मारना है और 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। उन्होंने अपने भाषण से प्रत्येक कार्यकर्ता में जोश भर दिया और सभी को भारत माता के नारे लगवाए। धरने में जयपुर के विभिन्न कोनों से आई सैकड़ों की संख्या में नारी शक्ति भी उपस्थित रही।

■ **प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्वर्गीय मां के खिलाफ इन दोनों नेताओं द्वारा की गई अभद्र टिप्पणियों की भाजपा कार्यकर्ताओं ने घोर निंदा की**

■ **''मां का अपमान कांग्रेस की पहचान'' तथा ''मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान'' लिखित तख्तियों के साथ धरने में शामिल हुई मातृशक्ति**

वे ''मां का अपमान कांग्रेस की पहचान, ''मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान'' लिखित तख्तियों के साथ धरने में शामिल हुई। इस अवसर पर अनेक विधायक और वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने भाषण में राहुल गांधी व तेजस्वी यादव की घोर निंदा की।

इस अवसर पर सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा, हवामहल से विधायक बालमुकुंदचार्य, किशनपोल प्रत्याशी चंद्रमोहन बँटवाडा, महापौर कुसुम यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी, प्रदेश मंत्री अजीत माण्डन, प्रदेश कार्यालय मंत्री मुकेश पारीक, पूर्व विधायक मोहन लाल गुप्ता, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री जयश्री गर्ग, प्रदेश मंत्री स्टेफी चौहान, अपूर्वा सिंह, राजस्थान राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा, सहित अनेक पार्षद एवं मंडल अध्यक्ष, सही समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।

अतिवृष्टि,फसल खराबे और लॉ एण्ड ऑर्डर पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस

जयपुर के कांस्टीट्यूशन क्लब में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक

जयपुर। राजधानी जयपुर के कांस्टीट्यूशन क्लब में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक से विधायक सचिन पायलट भी शरीक हुए।

बैठक में रणनीति बनाई गई कि, राजस्थान में अतिवृष्टि से बिगड़े हालातों, फसल खराबे और प्रदेश में लॉ एण्ड ऑर्डर को लेकर सदन में भाजपा सरकार को घेरा जाये। बैठक में करीब-करीब सभी कांग्रेस विधायक पहुंचे, जिन्हें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने और अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाने के निर्देश दिये।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि पूरा विपक्ष जनसमस्याओं को विधानसभा में उठाकर सरकार को कटघरे में खडा करेगा। जूली ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने बैठक में बताया है कि अतिवृष्टि से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। गरीबों के कच्चे मकान ढह गये है,खेतों में पानी भरने से किसान बर्बाद हो गये है। पूरे प्रदेश में सड़कों की हालत बदत्तर है। इसके बावजूद भी सरकार ने कोई राहत पहुंचाने का कार्य नहीं किया है।

शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम से छेड़छाड, अंग्रेजी स्कूलों को बंद करने तथा झालावाड़ की स्कूल में हुए हादसे को लेकर भी कांग्रेस गंभीर है। सरकार पंचायतीराज और निकाय चुनाव करवाने से बच रही है। परिसीमन के नाम पर लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है।

महिला व बालिका अत्याचार के मामले दिनोदिन बढ़ते जा रहे है,प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। इन्ही तमाम मुद्दो को लेकर कांग्रेस, सदन में राज्य सरकार को घेरेगी।

ए.आई.सी.सी. महासचिव सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हो या राजस्थान की भजनलाल सरकार, इनका रवैया यही रहा है कि ये लोग मुद्दो पर बात ही नहीं करना चाहते। प्रदेश में बाढ़ के हालात है, जनजीवन अस्त-व्यस्त है, किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे है जिन पर कांग्रेस सदन में सार्थक चर्चा चाहती है।

उन्होंने कहा कि हमें विधानसभा में चुनकर भेजा है तो जनता चाहती है कि हम उनकी समस्याओं पर सदन में चर्चा करे। भजनलाल सरकार ने दो साल के शासन में प्रदेश में कोई काम नहीं किया,इसलिए हम सदन में सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे।

याचिका खारिज

जयपुर । हाईकोर्ट ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और नियंत्रक पद पर डॉ. दीपक माहेश्वरी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. अवतार सिंह दुआ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने दीपक माहेश्वरी की ओर से साल 2016 में दिए त्यागपत्र और उसे वापस लेने के आधार पर उनकी नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने इस तथ्य की जानकारी होने के भी चयन प्रक्रिया में भाग लिया और असफल होने पर सात साल पहले दिए इस्तीफे और उसे वापस लेने की अनुमति देने पर आपत्ति उठा रहा है।

एलआईसी की बीमा बाजार में 65.83 प्रतिशत हिस्सेदारी

जयपुर। भारत की अग्रणी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) अपनी 69वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। एलआईसी ने 36 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करते हुए सबसे तेज़ी से बढ़ते भारतीय ब्रांड के रूप में भी उभरी है। गत 1 सितंबर 2025 को अपनी 69वीं वर्षगांठ का गौरवशाली क्षण मना रही एल.आई.सी. ने अपनी उपलब्धि का श्रेय टीम के समर्पण और कड़ी मेहनत तथा ग्राहकों के विश्वास को दिया है।

एल.आई.सी. वित्तीय वर्ष 2024-25 में पॉलिसियों में 65.83 प्रतिशत बाज़ार हिस्सेदारी और प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय में 57.05 फीसदी बाज़ार हिस्सेदारी के साथ बाज़ार में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है। कुल एयूएम 6.45 प्रतिशत बढ़कर 54.52 लाख करोड़ रुपये हो गया है।वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम 35 व्यक्तिगत उत्पादों, 12 समूह उत्पादों, 7 व्यक्तिगत राइडर्स और 1 समूह राइडर का एक व्यापक पोर्टफोलियो प्रदान करता है, जो समाज के हर वर्ग की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे एंडोमेंट इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, चाइल्ड इंश्योरेंस, एन्युटी प्लान, ग्रुप इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस, हेल्थ और यूनिट लिंक्ड उत्पाद। ये योजनाएँ ऑफ़लाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं।

इसके अलावा एलआईसी का स्वर्ण जयंती फाउंडेशन (जीजेएफ), एलआईसी की सामुदायिक सेवा पहल के एक भाग के रूप में वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था और अब तक 926 परियोजनाओं में 283 करोड़ रुपये और 80.62 करोड़ रुपये की 30835 छात्रवृत्तियाँ वितरित कर चुका है।

विदेशी पर्यटकों के लिए जी.एस.टी. हटाने की मांग

जयपुर (कासं)। इंडियन हैरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए) ने भारत सरकार के पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को एक ज्ञापन सौंपकर विदेशी पर्यटकों के लिए जीएसटी हटाने की मांग की है। इस कदम से इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया और इजराइल जैसे गंतव्यों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। इससे अमेरिकी टैरिफ के मौजूदा मुद्दों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा घाटे की भरपाई में भी मदद मिलेगी। यह बात आईएचएचए के सेक्रेटरी जनरल, कैप्टन गज सिंह अलसीसर ने मंगलवार को अलसीसर हवेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही।

■ **इंडियन हैरिटेज होटल्स एसो. का 12वां एनुअल कन्वेंशन और 24वीं जनरल मीटिंग 6-7 सितंबर को होगी**

उन्होंने बताया कि इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन की 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग और 12वां एनुअल कन्वेंशन इस वर्ष जयपुर स्थित कासल कानोता में 6 से 7 सितंबर को आयोजित होगा। कार्यक्रम में पूरे भारत से लगभग 150 हेरिटेज होटेलियर्स के शामिल होने की उम्मीद है। कैप्टन अलीसार ने बताया कि पिछले वर्ष हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने के लिए की गई आईएचएचए की मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसे अपने बजट में घोषित भी कर दिया गया है। साथ ही, इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

आईएचएचए कमेटी सदस्य, शत्रुंजय सिंह ने कहा कि इस वर्ष के आईएचएचए कन्वेंशन की थीम रोमांटिक हैरिटेज है। हेरिटेज प्रॉपर्टीज में स्वाभाविक रूप से रोमांस की भावना समाहित होती है, जो उनकी कलिनरी परम्पराओं, म्यूजिक, आर्किटेक्चर और इक्वेस्ट्रियन संस्कृति में प्रतिबिम्बित होती है।

कासल कानोता के संरक्षक पृथ्वी सिंह कानोता और प्रताप कानोता ने बताया कि एनुअल कन्वेंशन के पहले दिन 6 सितंबर (शनिवार) को राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी दीप प्रज्वलित कर एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर आईएचएचए के प्रेसिडेंट एमिरेट्स, एचएच महाराजा गज सिंह; आईएचएचए के महासचिव, कैप्टन गज सिंह अलसीसर; आईएचएचए के उपाध्यक्ष, स्टीव बोर्जिया सहित राजस्थान सरकार के पर्यटन अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन सत्र के दौरान संजीव विद्यार्थी द्वारा रिवाइवल ऑफ हेरिटेज आर्किटेक्चर विषय पर चर्चा आयोजित होगी। इसके पश्चात, अभिमन्यु सिंह अलसीसर द्वारा राजस्थान के लोक संगीत पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की जाएगी। इसके अतिरिक्त, वीर विजय सिंह डुंडलोद द्वारा होटल ऑपरेशंस पर एक संवाद और सोलर एज टेक्नोलॉजीस द्वारा एक प्रजेंटेशन प्रस्तुत की जाएगी। दिन के दौरान एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होगी, जिसमें भारत सरकार के पर्यटन मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत शिरकत करेंगे और सदस्यों को संबोधित करेंगे। इस बैठक में केवल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य हिस्सा लेंगे।

सचिन पायलट ने जैसलमेर पहुंचकर कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि दी

ए.आई.सी.सी. महासचिव पायलट ने, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने के विवाद को लेकर राजस्थान सरकार पर भी निशाना साधा

जयपुर/जैसलमेर (कासं)। ए.आई.सी.सी. महासचिव और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को जैसलमेर के मोहनगढ़ पहुंचकर पूर्व सांसद स्व. कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतृप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। पायलट के साथ मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद थे। जब पायलट विशेष विमान से जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उनके स्वागत में पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद, पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर, पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर, पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर व अंजना मेघवाल और सैकड़ों कार्यकर्ता उमड़े।

ए.आई.सी.सी. महासचिव और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को जैसलमेर के मोहनगढ़ पहुंचकर पूर्व सांसद स्व. कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतृप्त परिजनों को ढांढस बंधाया।

■ **पायलट ने कहा कि ''एस.आई. भर्ती परीक्षा को लेकर लम्बे समय से विवाद चल रहा था, परंतु राजस्थान सरकार कभी कहती रही कि है कमेटी बना दी... समिति बना दी। लेकिन हकीकत में सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।''**

कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सचिन पायलट पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव के जैसलमेर आवास पर पहुंचे। जहां मीडिया से मुख़ातिब होते हुए सचिन पायलट ने एस.आई. भर्ती परीक्षा रद्द करने के मामले पर राज्य सरकार पर जुबानी हमला बोला। पायलट ने कहा कि, प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। एस.आई. भर्ती परीक्षा को लेकर लम्बे समय से विवाद चल रहा था, परंतु सरकार कभी कहती रही कि है कमेटी बना दी... समिति बना दी। लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सरकार को अब तक यह भी मालूम नहीं कि, करना क्या है। सरकार बोलती कुछ है और कोर्ट में हलफनामा कुछ और देती है। यह पूरा कन्फयूजन सरकार के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो परीक्षा में सफल रहे, जिनकी नौकरी लगी। अब कोर्ट से आदेश आया है, उसमें भी कन्फ्यूजन है। सचिन पायलट ने कहा कि, राजस्थान सरकार को तुरंत प्रभाव से निर्णय लेकर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के इस पूरे मामले को स्पष्ट करना चाहिए। मैंने पूर्व में भी बार-बार कहा है, आज भी दोहरा रहा हूं कि यह समस्या मात्र एक परीक्षा की नहीं है, अपितु इस पूरे सिस्टम की है। आर.पी.एस.सी. वो गंगोत्री है, जहां से परीक्षाएं व इंटरव्यूज होते हैं और नौकरी लगती है। जैसा कि कोर्ट ने कहा कि आर.पी.एस.सी. में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे में उन सदस्यों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली पर भी संदेह होता है।

आपके घर हूपर नहीं आ रहा तो क्यूआर कोड स्कैन करे

जयपुर । उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने मंगलवार को जयपुर में ''वॉयसेज़ ऑफ भारतः युवा फॉर सस्टेनेबिलिटी'' अभियान के तीसरे न्यूज़लेटर का विमोचन किया। उन्होंने सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में जयपुर में प्रस्तावित दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में भी आमंत्रण स्वीकार किया।

इस एक वर्षीय अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून 2025 को की थी। ''वॉयसेज़ ऑफ भारतः युवा फॉर सस्टेनेबिलिटी'' का उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कहानी कहने, पॉडकास्ट, वीडियो और डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रेरित और प्रशिक्षित करना है। अभियान के तहत अब तक कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें वेबिनार श्रृंखला और 21 जुलाई 2025 को कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय, जयपुर में आयोजित पहला राष्ट्रीय युवा स्थिरता सम्मेलन शामिल है।

ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करने के बाद भी वकील को क्यों दिखाया असफल?

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2012 में ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करने के बाद वकालत कर रहे वकील को अब इस परीक्षा को पास नहीं करने वालों की सूची में शामिल करने पर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सचिव को 9 सितंबर को तलब किया है। अदालत ने कहा है कि सचिव व्यक्तिगत या वीसी के जरिए पेश होकर प्रकरण से अदालत को अवगत कराए। अदालत ने इस दौरान संबंधित रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया से भी जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश भागीरथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा और अधिवक्ता अक्षय शर्मा ने अदालत को बताया कि बीसीआर ने साल 2012 में याचिकाकर्ता का नामांकन पर स्थाई वकालत के लिए उसे प्रमाण पत्र जारी किया गया। वहीं बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने 2010 के नियमों को लागू करते हुए साल 2012 में ऑल इंडिया बार एग्जाम आयोजित किया। जिसमें याचिकाकर्ता शामिल होकर परीक्षा में पास हुआ। इस पर याचिकाकर्ता ने बीसीआई से प्रैक्टिस प्रमाण पत्र मांगा।

जिस पर कौंसिल ने उससे ढाई हजार रुपए का शुल्क जमा करवाया। याचिका में कहा गया कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने एक सूची जारी कर ऑल इंडिया बार एग्जाम पास नहीं करने वाले वकीलों को प्रैक्टिस प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया। इस सूची में याचिकाकर्ता का नाम भी शामिल किया गया, जबकि वह पूर्व में ही यह परीक्षा पास कर चुका है। याचिका में कहा गया कि इसकी शिकायत बार कौंसिल ऑफ इंडिया में करने पर उसे सूचित किया गया कि ऑल इंडिया बार एग्जाम में फेल हुआ था। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि उसे पहले पास बताया गया और प्रमाण पत्र जारी करने के बदले फीस भी ली गई। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बीसीआर के सचिव को पेश होने के आदेश दिए हैं।